चीन का दोहरापन

पुलवामा के भयावह हमले के बाद भी पाकिस्तान के आतंकी सरगना मसूद अजहर को चीन बचाने की कोशिश में लगा हुआ है. चीन अजहर को सुरक्षा परिषद की पाबंदी से दो बार बचा चुका है. अपने रवैये पर कायम रहते हुए उसने भारत से अजहर के खिलाफ सबूतों की मांग की है, जो उसकी हेठी और दोहरे मानदंड का परिचायक है. चीन अपने देश के भीतर झिनजियांग प्रांत में चरमपंथी अलगाववादी गुटों की हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध कई सालों से अभियान चला रहा है. स्वायत्त क्षेत्र होने के बावजूद वहां सरकार ने नागरिक अधिकारों की परवाह किये बिना बड़ी संख्या में लोगों को जेलनुमा शिविरों में रखा है, जहां उन्हें कठोरता से मानसिक तौर पर सरकारी विचारधारा और नीतियों के लिए तैयार किया जाता है. आतंकियों को मौत की सजा देने और कैद में रखने की कवायद भी जारी है. सरकार की कोशिश है कि चरमपंथ को संगठित आतंकवाद में बदलने से पहले ही खत्म कर दिया जाये. चीन 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी गिरोहों से संपर्क कर उग्यूर आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर बंद कराने और बाहरी मदद को रोकने की कोशिश करता रहा है. वर्ष 2000 में पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने तालिबान के मुखिया मुल्ला उमर से मुलाकात कर यह गारंटी हासिल की थी कि उग्यूर आतंकी झिनजियांग में हमले नहीं करेंगे. इसके बदले उन्हें तालिबानियों की तरफ से लड़ने की छूट देने पर चीन मान गया था. आतंकवाद पर दोहरेपन का एक बड़ा कारण यह भी है कि पाकिस्तान में चीन को अपने 60 बिलियन डॉलर की परियोजनाओं तथा उनमें कार्यरत चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है. इसके लिए उसने अल-कायदा और तालिबान से जुड़े संगठनों के साथ बलोच उग्रवादियों और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को साधने की नीति अपनायी है. तालिबान से शांति-वार्ता करने और अफगानी सत्ता में उसकी हिस्सेदारी पर चीन का जोर इसी वजह से है. अन्य इलाकों के अलावा न सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और पाक-अधिकृत कश्मीर में चीनी आर्थिक गलियारे का विस्तार हो रहा है, बल्कि इसके तहत मसूद अजहर के ठिकाने बहावलपुर में एक बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी बन रहा है. इस प्रकार दक्षिण एशिया में चीनी वर्चस्व स्थापित करने की नीति और आतंक को इस्तेमाल करने की पाकिस्तानी राजनीति के बीच एक गठजोड़ बन चुका है. यह गठजोड़ भारत, ईरान और अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है. ये आतंकी पाकिस्तान के भीतर भी निर्दोष नागरिकों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते रहे हैं. चीन की गोद में खेल रहे आतंकवादी किसी दिन उसी के लिए भस्मासुर बन सकते हैं. आज जरूरत इस बात की है कि चीन अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के साथ पाकिस्तान के रवैये में बदलाव के लिए भी पुरजोर कोशिश करे.

दक्षिण एशिया में चीनी वर्चस्व स्थापित करने की नीति और आतंक को इस्तेमाल करने की पाकिस्तानी राजनीति के बीच एक गठजोड़ बन चुका है.

सतर्क-सजग रहे भारत

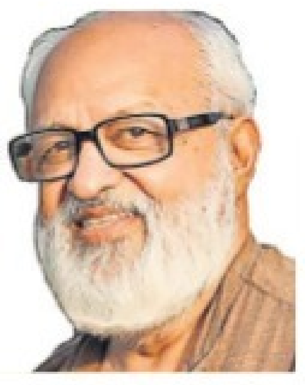

पुष्पेश पंत
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
pushpeshpant@gmail.com

सऊदी युवराज मुहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा को लेकर सरकारी हलकों में बहुत उत्साह देखने को मिला. विदेश मंत्रालय का यह दावा था कि भारत की आपत्ति को ध्यान में रखकर ही यह शाही मेहमान पाकिस्तान से भारत नहीं आये, बल्कि वापस रियाद लौटने के बाद ही उन्होंने दक्षिण एशिया के दौरे का दूसरा कदम उठाया. पर इस बात को कैसे नजरंदाज करें कि इस क्षेत्र के दौरे का आरंभ पुराने मित्र और सऊदी सहायता समर्थन पर आश्रित पाकिस्तान से हुआ और भारत के बाद सीधे वह चीन गया?

सऊदी विदेश मंत्री का बयान भी उल्लेखनीय है. उनका कहना था कि युवराज का प्रयास भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव घटाने का रहेगा. यह समझ पाना कठिन है कि पाकिस्तान के प्रति पारंपरिक पक्षधरता दर्शानेवाला तथा वहां कट्टरपंथी वहाबी इस्लाम के प्रसार में निर्णायक भूमिका निभानेवाला देश यह कैसे कर सकता है?

यह बात रेखांकित की जा रही है कि शाही दौरे के दौरान पांच बड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि सऊदी अरब के विश्व दर्शन में बदलाव आ रहा है और वह भारत के साथ दूरदर्शी सामरिक समझौते के लिए तैयार है. हिंद महासागर में नौसैनिक गश्त लगानेवाला समझौता सबसे अहम है. तेल शोध के क्षेत्र में काम करनेवाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने सऊदी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय वार्ताएं कीं और यह अपेक्षा की जा रही है कि ईरान पर लगाये अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए सऊदी हमारा साथ होगा. याद दिलाना जरूरी नहीं कि सऊदी अरब से भारत सबसे बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है. निश्चय ही उससे बेरुखी हमारे हित में नहीं है.

मगर यहां तत्काल यह जोड़ने की जरूरत है कि तेल की राजनीति ही इस देश के साथ हमारे संबंधों को संवेदनशील नहीं बनाती. मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का और मदीना भी सऊदी अरब में ही स्थित हैं और इनके रखवाले के रूप में वही हज यात्रा का प्रबंधन करता है. भारत में मुसलमानों की आबादी दुनिया के किसी भी बडे इस्लामी देश की तुलना में कम नहीं है. जनतांत्रिक चुनावी राजनीति के दबाव में किसी भी राजनीतिक दल के लिए सऊदी अरब के साथ दोस्ताना रिश्ते उपयोगी महसूस होते हैं.

कुछ और बातों का जिक्र बेहद जरूरी है. जिस समय युवराज मुहम्मद बिन सलमान का अभिषेक हुआ था, यह आशा की जा रही थी कि दकियानूसी से ग्रस्त सऊदी अरब में आधुनिकता तथा उदारवाद की नयी लहर उठ रही है. युवराज ने शुरू में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कड़े कदम उठाये, उन्होंने इस धारणा को पुष्ट किया. राजपरिवार से जुड़े अब तक ताकतवर दरबारियों को (शाही) जेल भेजने में उन्होंने देर नहीं लगायी और महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दे दिया. अपनी प्रजा को इंटरनेट का सुख (सीमित ही सही) भोगने का अवसर निकट भविष्य में देने की पेशकश भी उन्होंने की. सऊदी शाह के साथ उन्होंने रूस का दौरा किया और यह संकेत दिया कि वह अमेरिका की छाया से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं.

सऊदी आचरण में बदलाव का विश्लेषण करनेवाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस हृदय परिवर्तन का मुख्य कारण तेल की कीमतों में गिरावट तथा कार्बन प्रसरण को लेकर जीवाश्म ईंधन में कटौती तथा तेल की निरंतर कम होती खपत से जुड़ी आशंकाएं हैं. कभी बेशुमार अमीर समझा जानेवाला यह देश आज अपने भोग-विलासी खर्च में झिझकता दिख रहा है. बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों, पेशेवरों को नये करों के बोझ से वहां रहना दूभर हो रहा है. कई छंटनी के शिकार हो घर लौटने को मजबूर हुए हैं. भारत के लाखों नागरिक सऊदी अरब में बरसों से काम करते आये हैं, इन सबका भविष्य संकटग्रस्त लग रहा है.

सऊदी अरब के सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्व को चुनौती देनेवाला नया आक्रामक रूप से कट्टरपंथी संगठन आईएसआईएस यानी बगदादी की नयी खिलाफत भी सीरिया तथा शम्स में सऊदी अरब के लिए सरदर्द पैदा करता रहा है. इन सब बातों का लुब्बो-लुवाब यह है कि शिखर पर सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय परिवेश भी सऊदियों के लिए पहले जैसा अनुकूल नहीं रहा. ईरान, लेबनान और रूस के संयुक्त मोर्चे ने निश्चय ही उनके वर्चस्व को चुनौती दी है. दक्षिण एशिया और चीन की तरफ दृष्टिपात की प्रेरणा यही है.

अंत में इस बात को भुलाना असंभव है कि सऊदी मूल के अमेरिकी पत्रकार खशोगी की तुर्की में सऊदी दूतावास में हत्या के बाद युवराज सलमान विवादों के घेरे में रहे हैं. अमेरिका तथा ब्रिटेन इस बात को कबूल कर चुके हैं कि खशोगी की निर्मम हत्या के अभियुक्त सऊदी युवराज के अंतरंग अनुचरों में थे और इस हत्या की साजिश उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही रची गयी थी. यदि यह बात मान भी लें कि इस वारदात को अति उत्साही बेलगाम दरबारियों ने अंजाम दिया, तब भी इस बारे में आश्वस्त होना कठिन है कि निरंकुश राजतंत्र में तुनकमिजाज शासक के व्यक्तिगत फैसलों या उसके विश्वासपात्र अधिकारियों के अवसरवादी उतावले आचरण के क्या अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं. भारत के लिए सतर्क-सजग रहना ही समझदारी होगी.

दुर्भाग्य से इस यात्रा को ग्रहण लगानेवाले पुलवामा के आतंकवादी हमले ने रही-सही कसर पूरी कर दी. भारत सतर्क और सजग रहकर ही तेजी से बदलते परिप्रेक्ष्य में अपने राष्ट्रहित सुरक्षित रख सकता है.

हमारे लिए यह समझना परमावश्यक है कि सऊदी अरब तथा अमेरिका के सामरिक और आर्थिक रिश्ते आधी सदी से भी अधिक पुराने हैं. इन्हें युवराज सलमान चाहें भी तो पलक झपकते नहीं बदल सकते. वह बदलना चाहेंगे भी क्यों? उनकी प्राथमिकता अपनी छवि को संवारना-सुधारना है और स्वदेश में अपनी राजनयिक सक्रियता से आलोचकों का मुंह बंद करना है. वैसे राजशाही में जनमत का कोई महत्व होता नहीं, तख्तनशीं शासक ही सर्वशक्तिमान होता है. यह सुझाना तर्कसंगत है कि भारत को ईरान तथा इस्राइल से विमुख करने के लिए ही यह विकल्प सार्वजनिक रूप से विज्ञापित किया जा रहा है. अफगानिस्तान में असफलता के बाद अमेरिका भी यह स्वीकार करने को बाध्य हुआ है कि तालिबान तबके से संवाद करना होगा. सऊदी-पाकिस्तानी-अमेरिकी-चीनी हितों का सन्निपात भारत के अनुकूल नहीं और आनेवाले समय में भी प्रतिकूल ही रहेगा.

भारत के लिए यह समझना परमावश्यक है कि सऊदी अरब तथा अमेरिका के सामरिक और आर्थिक रिश्ते आधी सदी से भी अधिक पुराने हैं. इन्हें युवराज सलमान चाहें भी तो पलक झपकते नहीं बदल सकते.

इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ

संदीप बामजई
आर्थिक मामलों के जानकार
delhi@prabhatkhabar.in

एक तरफ भारत सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 7.5 प्रतिशत रहेगा, वहीं नोमूरा ने कहा है कि सरकार की वित्तीय नीतियां ऐसी नहीं हैं, जो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा सकें. नोमुरा के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 प्रतिशत से भी कम रहेगा. बहरहाल, कितना ग्रोथ होगा, यह तो आनेवाले वक्त में ही पता चल पायेगा. और आनेवाले दिनों में इस संबंध में कई बातें भी सामने आयेंगी.

नोमुरा ने जो जीडीपी का आकलन किया है, उसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं. इन कारणों को अच्छी तरह समझने की जरूरत है. अर्थव्यवस्था का मूल यही है कि सरकार की आय कितनी है और उसका खर्च कितना है. बेहतरीन अर्थव्यवस्थाएं वो होती हैं, जिनकी आय ज्यादा और खर्च कम होते हैं. हमारे घरों में भी यही तथ्य काम करता है और हम अपनी आय ज्यादा चाहते हैं, जबकि हर हाल में खर्च को कम रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन, इस समय भारत सरकार का खर्च ज्यादा है और आय कम, इसलिए अर्थव्यवस्था की कुछ चुनौतियां तो हैं ही. दरअसल, हम बड़े निर्यातक देश नहीं हैं, बल्कि उपभोग करनेवाले देश हैं और सेवा देनेवाले देश हैं. इसलिए हमारे पास आमदनी की समस्या तो बनी ही रहेगी. सरकार के पास आय का स्रोत सिर्फ टैक्स है, जिसे बढ़ाये जाने की जरूरत है. यदि आय नहीं बढ़ेगी, तो वित्तीय घाटा बढ़ेगा. किसी भी सरकार के लिए वित्तीय घाटे को कम करने के लक्ष्य होने ही चाहिए. दरअसल, हमारी सरकारों को अपनी सभी जन-योजनाओं को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है. इस संदर्भ में यह खबर अच्छी है कि पिछले दिनों आरबीआई ने सरकार की मदद की है. आरबीआई ने सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये दिया है, ताकि सरकार का काम सुचारू रूप से चल सके. बीते साल सितंबर में भी आरबीआई ने सरकार की मदद की थी.

हम बड़ी और तेज गति से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था के साथ ही कुछ जरूरी चुनौतियों से भी होकर गुजर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है. इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान किया, उससे सरकार पर कुछ बोझ बढ़ा है. यह बोझ एक लाख करोड़ रुपये तक है और चूंकि यह खर्च है, इसलिए जरूरी यह है कि सरकार को आय भी आये, तभी संभव है कि वह वित्तीय घाटे को कम कर पायेगी. अगर आमदनी कम होगी और खर्च ज्यादा होगा, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. इसलिए कुछ चुनौतियां है सरकार के सामने, लेकिन वह इसे संभालने की कोशिश में फिलहाल सफल होती नहीं दिख रही है.

भारत की अर्थव्यवस्था में 67 प्रतिशत उपभोग का हिस्सा है. पिछले डेढ़-दो दशक में कई नयी ऐसी चीजें बदली हैं, जिसकी वजह से हमें आंकड़े निकालने की प्रक्रिया तो बदलनी ही पड़ेगी. इसलिए सरकार कह रही है कि डेटा को वह नये फॉर्मेट के आधार पर तय कर रही है. यह बात ठीक भी है, क्योंकि यह वक्त की जरूरत भी है कि हम अपने आंकड़ों-आकलनों को नयी प्रक्रिया के तहत शुद्धता के मानक पर ले आयें. लेकिन, यह ठीक नहीं कि सरकार अपने मुख्य सांख्यिकीविद् से कोई बात न कर खुद ही सब कुछ तय करे. सरकार और मुख्य सांख्यिकीविद् के बीच में संवादहीनता से सवाल तो उठेंगे ही. शायद यही सब देखते हुए ही नोमुरा ने अपना आंकड़ा दिया है.

भारत सरकार की उम्मीद हो या फिर नोमुरा का आकलन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी तथ्य हैं, क्योंकि इन्हीं सब आधार पर ही मार्केट में निवेशक निवेश करते हैं. जब निवेश बढ़ता है, तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ती है. किसी भी तरह के आंकड़े की शुद्धता जरूरी है, नहीं तो उस पर सवालिया निशान लगना तय है और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा. इसलिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े का संशोधन आज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. चूंकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़नेवाला देश बन गया है, इसलिए सरकार सोच रही है कि आंकड़े निकालने का आधार और प्रक्रिया आदि नये हों.

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार जीडीपी के डेटा को खुद ही संशोधित कर रही है. यहां तक कि पिछले साल के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को भी सरकार संशोधित कर रही है, ताकि यह दिखाया जा सके कि हम साढ़े सात प्रतिशत से ऊपर चल रहे हैं. इस मसले पर कई सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के डेटा संग्रहण के आधार पर ही जीडीपी ग्रोथ, मुद्रास्फीति और कई अन्य आंकड़े निकलते हैं. भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के मुख्य सांख्यिकीविद् ने कुछ दिन पहले ही यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि सरकार जीडीपी ग्रोथ के संशोधन खुद कर रही है. सांख्यिकीविद् ने कहा कि सरकार जब खुद यह डेटा बना रही है, तो फिर उसकी सत्यता संदिग्ध हो सकती है. हालांकि, इसमें दूसरी बात यह भी है कि पहले जो जीडीपी का डेटा था, वह बहुत पुराने फॉर्मेट में बना हुआ था. चूंकि अब भारत की अर्थव्यवस्था में कई नये आयाम जुड़ गये हैं और लगातार बढ़ते हुए हम एक उपभोग वाली अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं. इसलिए नये तरह से जीडीपी का डेटा निकालने की जरूरत भी महसूस की जा रही है. यह जरूरी भी है, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए.

जीडीपी ग्रोथ को लेकर भारत सरकार की उम्मीद हो या फिर नोमुरा का आकलन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी तथ्य हैं, क्योंकि इन्हीं सब आधार पर ही मार्केट में निवेशक निवेश करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था गति पकड़ती है.

बोधि वृक्ष

अपनी बुद्धिमत्ता

आजकल आप हर चीज को मशीन बना रहे हैं. सिर्फ आपके लिए 'उपयोगी' हो सके, एक मनुष्य के जीवन में इसके अलावा और भी आयाम होते हैं. यह जरूरी नहीं है कि एक मनुष्य किसी के लिए उपयोगी हो. बात सिर्फ यह है कि गाड़ी में बंधे बैल जंगल में छलांगे मारते हिरनों को देखकर सोचते हैं, 'वे अपना जीवन बरबाद कर रहे हैं, किसी के लिए कोई काम के नहीं हैं, बेकार हैं'. लेकिन हिरन मौज में हैं, आनंद कर रहे हैं. आप बंधे हुए हैं और आप में कोई आनंद नहीं है. उपयोगी होने के प्रयत्न में अगर आप एक आनंद-रहित मनुष्य हो जाते हैं, तो जीवन के सभी उद्देश्य हार जाते हैं. आप क्या कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता. समाज की नजर में चाहे आपको वैसा चेहरा लेकर घूमने के लिए, और आप ने दुनिया के लिये जो कुछ भी किया है, उसके लिये शायद कुछ इनाम मिल जाये लेकिन जीवन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है. अपने जीवन को किसी और की बुद्धिमत्ता से देखना नहीं चाहिए. अपने जीवन को थोड़ी ज्यादा बुद्धिमत्ता से देखना सीखिये. हर-एक के पास अपने जीवन को संवेदनशीलता के साथ देखने की बुद्धिमत्ता होती है. समस्या यह है कि आप भूतकाल के और वर्तमान के भी आदर्श, सफल व्यक्तियों से बहुत प्रभावित होते हैं. हर सामान्य बच्चा एक पूर्ण जीव की तरह होता है. आप एक बच्चे को सिर्फ उसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए पोषित कर सकते हैं. आप उनको कुछ और नहीं बना सकते. अगर आपके ख्याल में नारियल का वृक्ष ही एक आदर्श वृक्ष हो और आप के बगीचे में एक आम का पौधा उग आता है, तो आप क्या करेंगे? चूंकि यह नारियल के वृक्ष की तरह नहीं दिखता, तो क्या आप उसकी सिर्फ एक सीधी डाल छोड़ कर बाकी सब काट डालेंगे? यह तो बहुत गलत बात होगी. ऐसे ही, आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि बच्चे को उसकी पूर्ण बुद्धिमत्ता, शारीरिक खुशहाली तथा भावनात्मक खुशहाली प्राप्त करने के लिए पोषित करें. यह तभी होगा, जब आप उसको सिर्फ पोषण दें, उससे छेड़छाड़ न करें.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

आपके पत्र

नामवर जी को श्रद्धांजलि

अहले सुबह रेडियो पर सुना कि महान आलोचक, लेखक, कवि, शिक्षक, पत्रकार एवं साहित्यकार डॉ नामवर सिंह का देहांत हो गया. मन व्यथित हो गया. अभी पिछले महीने ही कृष्णा सोबती जी के निधन की मनहूस खबर मिली थी. पिछले डेढ़ वर्ष के भीतर ही, साहित्य जगत के कई दिग्गज हस्ताक्षरों का सितारा अस्त हो गया. डॉ नामवर सिंह जी साहित्य की तमाम विधाओं में पारंगत तो थे ही, मगर वे सबसे पहले एक आलोचक थे. उनका झुकाव साम्यवाद के ओर था. यह किसी से छुपा नहीं है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन के समय ही लोकसभा का चुनाव भी लड़े और हार गये. फिर जोधपुर विश्वविद्यालय गये. जेएनयू के हिंदी विभाग की नींव तो डॉ नामवर सिंह ने डाली थी. डॉ नामवर सिंह को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि !

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी,जमशेदपुर

पाक पीएम का बेतुका राग

पुलवामा आतंकी हमले के पांच दिन बाद पाकिस्तान ने मुंह खोला है और वही सबूतों का पुराना राग अलापा है. भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान और आइएसआइ का हाथ है, लेकिन पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से साफ इंकार कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले भारत सबूत दे, उसके बाद पाकिस्तान कार्रवाई करेगा. इमरान के अनुसार भारत हर बार पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाता है. पहले भी कई बार सबूत दिया जा चुका है. लेकिन वह आतंकवादी हाफिज सईद पर कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है. मुंबई हमले व उरी हमले के बाद भी पक्के सबूत दिये गये थे, लेकिन तब भी पाकिस्तान ने इन सबूतों को ही मानने से इनकार कर दिया था. इमरान ने भारत के साथ बातचीत की उम्मीद जताई लेकिन पाक पीएम को यह नहीं भूलना चाहिए कि सीमा पर गोलीबारी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती.

अमन सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश

सरकारी आंकड़े और बयानबाजी

सीमा पर मरते जवानों के आंकड़े और सरकार की बयानबाजी में कोई तालमेल नहीं दिखती है. सरकार कहती है कि बारामुला को आतंकियों से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है, परंतु सीमा पर या कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मरते जवानों की बढ़ती संख्या के आंकड़े सरकारी दावों की कलई खोलकर रख देते हैं. इसी फरवरी में गृह राज्य मंत्री द्वारा जो आंकड़े भारत की लोकसभा के पटल पर रखे गये, उसमें यह बताया गया है कि कश्मीर में 2014 से 2018 के बीच जवानों के शहीद होने की संख्या 94 प्रतिशत तक दुःखदरूप से बढ़ गयी है. यह कठोर और कटु सच्चाई है कि किसी भी सेना या सुरक्षाबल की सफलता की दर उसके खुफिया तंत्र की सटीक जानकारी से बहुत कुछ बढ़ जाती है, परंतु कश्मीर के मामले में भारत का खुफिया एजेंसियां बिल्कुल नाकाम रहीं हैं, जिसका खामियाजा जवानों को शहीद होकर देनी पड़ रही है.

निर्मल कुमार शर्मा ,गाजियाबाद

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है

कुछ अलग

रिश्ते भी स्मार्ट होने चाहिए!

मुकुल श्रीवास्तव
टिप्पणीकार
sri.mukul@gmail.com

आजकल स्मार्ट होने का जमाना है. वह चाहे फोन हो या टीवी या फ्रिज सब स्मार्ट होने चाहिए. वैसे स्मार्ट होने में कोई बुराई भी नहीं है. नया स्मार्टफोन लेने के बाद क्या आपको पुराने फोन की कमी खलती है? आप कहेंगे हां, कभी-कभी जब नया फोन हैंग होता है या कोई वायरस आ जाता है. वह बहुत सिंपल था, उसमें फीचर्स कम थे. यह नया फोन वैसे तो बहुत बढ़िया है, पर इसमें फीचर्स इतने ज्यादा हैं कि आधे की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है. खैर जब इतनी चीजें स्मार्ट हो रही हैं, तो हमारे रिश्ते क्यों न स्मार्ट हों? अब आप कहेंगे कि रिश्ते और स्मार्ट, यह भला कैसी बात हुई?

जब दुनिया बदल रही है, तो हमारे रिश्ते क्यों नहीं? बस यहीं मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है. कुछ चीजें अपने मूल रूप में ही अच्छी लगती हैं और हमारे रिश्ते उनमें से एक हैं. जरा सोचिये, हमारा पुराना फोन बात करने और मैसेज भेजने के काम तो कर ही रहा था और हममें से ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन से भी वही काम करते हैं, जो अपने पुराने फोन से करते थे. फोन पर चैटिंग और मिनट-मिनट पर फेसबुक का इस्तेमाल बस थोड़े दिन ही करते हैं फिर जिंदगी की आपाधापी में ये चीजें बस फोन का फीचर भर बनकर रह जाती हैं, पर इस थोड़े से मजे के लिए हम अपने फोन को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं. कहीं गिर न जाये, महंगा फोन कहीं खो न जाये, इसलिए हमेशा अपने से चिपकाये फिरते हैं.

हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपने फोन बदल कर गलत किया. रिश्ते भी वक्त के साथ बदलते हैं, पर जो चीजें नहीं बदलती हैं- वे हैं अपनापन, रिश्तों की गर्मी और किसी के साथ से मिलनेवाली खुशी. हमारा फोन स्मार्ट हुआ, तो जटिल भी हो गया. रिश्तों में भी अगर स्मार्टनेस आ जाये, तो उसमें जटिलता बढ़ जाती है, भले ही रिश्ते बने रहें, पर उनमें अपनापन और प्यार नहीं रह जाता.

हम जिंदगी में कई तरह के रिश्ते बनाते हैं, कुछ पर्सनल तो कुछ फॉर्मल. कभी आपने महसूस किया है कि हम फॉर्मल रिश्तों में ज्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं और अपने से अलग हटकर बरताव करते हैं. किसी बात पर गुस्सा भी आया, तो हंसकर टाल गये. कुछ बुरा लगा तो भी चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े रहे. जाहिर है, हम ऐसे नहीं होते और अगर अपने लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ होता, तो हम जमकर गुस्सा करते. लेकिन, बाहर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि जिनके साथ हम थे, उनसे हमारे औपचारिक रिश्ते थे. जाहिर है अपने लोगो से स्मार्टनेस दिखाने का कोई फायदा नहीं है. ये लोग हमारे अपने हैं, जो हमारी सब अच्छाई-बुराई जानते हैं. ये हमारे नाम, ओहदे, रसूख के कारण हमारे साथ नहीं हैं. ऐसे रिश्तों के साथ कोई नियम व शर्तें नहीं लागू होती हैं. अब समझ में आ गया होगा कि स्मार्टफोन खरीदते वक्त नियम-शर्तें जरूर पढ़ें, पर जब बात अपनों की हो, तो बिलकुल स्मार्टनेस न दिखायें, क्योंकि अपने रिश्तों के साथ कोई नियम और शर्तें नहीं होती हैं. तो मैं फोन भले ही स्मार्ट रखता हूं, पर असल में स्मार्ट हूं नहीं.

देश दुनिया से

कोरियाई प्रायद्वीप में रूस की भूमिका

कोरियाई प्रायद्वीप को लेकर रूस की नीति और अमेरिका-उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन पर उसका रुख क्या होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि मॉस्को अपनी कूटनीति और कूटनीतिक प्राथमिकताओं को किस रूप में देखता है. कोरियाई प्रायद्वीप रूस के नीति-निर्माण के लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है. अधिकांश रूसी अभिजात वर्ग का मानना है कि मॉस्को के पास उत्तर कोरियाई मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए आवश्यक राजनीतिक और आर्थिक लाभ का अभाव है और इसलिए प्रायद्वीप की गतिविधियों में वह सीमित भागीदारी चाहता है. हालांकि इस समय रूस, प्रायद्वीप के मामलों से अलग नहीं रहना चाहता है. रूसी अभिजात वर्ग का मानना है कि इस मुद्दे से रूस के अलग होने का मतलब है, पूर्वोत्तर एशिया के सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने से चूक जाना. रूस को उम्मीद है कि वह उत्तर कोरिया के परमाणु संकट में रणनीतिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा सकता है. वर्तमान में रूस केवल द्विपक्षीय कूटनीति के माध्यम से प्रायद्वीप मामलों में शामिल है, लेकिन रूसी विचारक भविष्य में सिक्स-पार्टी वार्ता को फिर से शुरू करने का समर्थन करते हैं.

GLOBAL TIMES

ली जून

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी